ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **September 22, 2018**

Shri Randeep Singh Surjewala, In-charge Communications Department, AICC addressed the media at AICC Hdqrs.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गाँधी जी ने बड़े महत्वपूर्ण और संगीन सवाल राफेल घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी से पूछे, मोदी जी तो चुप हैं, मौन मोदी बने बैठे हैं और जवाब में आया रक्षा मंत्रालय का एक बयान और कानून मंत्री का बयान प्रेस वार्ता के माध्यम से। चाटुकारिता, अंधभक्ति और अहंकार से भरे कानून मंत्री का चिड़चिड़ा चेहरा अक्सर तमतमाया रहता है और सिर सातवें आसमान पर, जब देश का कानून मंत्री ही गैर-कानूनी बात करे, जब देश का कानून मंत्री ही तर्कविहीन और न्यायसंगत बात ना कर पाए, तो भाजपा ये भूल ना जाए कि ये देश की जनता सब देख रही है। कानून मंत्री को चाहे जनता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते। परंतु मोदी सरकार को अर्श से फर्श तक का सफर अवश्य जवाबदेही ना देने के लिए जनता अवश्य उनकी धूल चटाएगी।

राहुल जी के सवालों का जवाब तो दिया नहीं, उस पर तो मोदी जी और उनके मंत्रियों ने चुप्पी साध ली। रक्षा मंत्री को काटे खून नहीं, दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही। चिड़चिड़े तरीके से केवल हमारी झूठी कमियाँ गिना रहे हैं। बात बड़ी सीधी है, 5 या 6 महत्वपूर्ण विषय कानून मंत्री ने कहे और मैं उनकी आपसे चर्चा करुंगा, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए सौ और झूठ भाजपा को बोलने पड़ रहे हैं।

A peeved and flummoxed Law Minister, Shri Ravi Shankar Prasad who has been a counsel for Shri Anil Ambani in the past, dished out a cacophony of slander and calumny to vent out his frustration and has tied himself in knots in verbal diarrhea of lies.

क्लेम नंबर 1, कानून मंत्री और रक्षा मंत्रालय दोनों ने ये कहा कि 30,000 करोड़ रुपए का ठेका अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को दिलाने में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। एक बात तो अब साफ कि प्रधान सेवक देश की नहीं, अनिल अंबानी जी की सेवा कर रहे थे। जवाब बड़ा सीधा है, फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति, जिन्होंने राफेल डील का समझौता किया, श्री ओलांद, उन्होंने mediapart.France को एक इन्ट्रव्यू में स्पष्ट तौर से कहा कि 36 जहाज खरीदने की शर्त ये थी कि 30,000 करोड़ रुपए का ठेका HAL से छीन कर अनिल अंबानी जी की रिलायंस समूह को दिया जाएगा और उन्होंने ये इन्ट्रव्यू में कहा और आज फिर उनके कार्यालय ने ये कहा कि फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ओलांद जिन्होंने ये समझौता किया था, वो अपने बयान पर अडिग हैं, उसे फिर दोहराया। ये भी साफ है कि ये डील दो व्यक्तियों, उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बीच हुई थी। तो जिनमें सौदा हुआ और जिससे सौदा हुआ, उनमें दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सामने आकर कह रहा है, तो दूसरा व्यक्ति चुप क्यों है?

<u>Claim 1</u> : *Law Minister & Defence Minister claim that PM Modi had no role in*

decision to grant Rs 30,000 Cr 'Offset Contract' to Shri Anil Ambani's Reliance Defence.

Answer 1: (i) The then French President, Mr. Francois Hollande clearly claimed in an interview 'Mediapart.fr' that in the new deal to purchase 36 aircrafts, Indian Government proposed Anil Ambani's Reliance Defence for the 'Offset Contract' and the French Government didn't have a choice but to accept it. **[Annexure A1]**. Admittedly, this 36 aircraft deal was negotiated between the French President, Mr. Francois Hollande & our Prime Minister, Shri Narendra Modi.

(ii) Neither Shri Narendra Modi, nor the French Government have stated that the then French President, Mr. Francois Hollande is not right. Even today, Mr. Hollande has re-confirmed his statement. Even Shri Ravi Shankar Prasad did not contradict it.

(iii) It is, thus, clear that PM, Shri Narendra Modi was sacrificing National Interests as also interests of Government Company, HAL and was serving the interests of Reliance Defence.

दूसरा हिस्सा, ना तो नरेन्द्र मोदी जी ने, ना फ्रांस की सरकार ने, ना भारत की सरकार ने, अब तक ये कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांस्वा ओलांद कुछ गलत कह रहे हैं। यानि उनकी सच्चाई पर कोई चुनौती नहीं। यहाँ तक कि कानून मंत्री भी उनके बात को काट नहीं पाए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि वो गलत कह रहे हैं। इसलिए एक बात साफ है कि ये चौकीदार देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता कर रहे थे, राष्ट्रहितों की रक्षा की बजाए निजी कंपनी के हितों को साध रहे थे। प्रधान सेवक देश की सेवा नहीं, वो सेवा कर रहे थे अनिल अंबानी जी की कंपनी की और इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा।

Claim 2:*As part of the conspiracy to obfuscate and divert, Law Minister & Defence Ministry referred to a news article of February 2012 to say that Dassault Aviation had signed a contract with Shri Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited to execute the offset contract.*

Answer 2: (i) This is totally false and utter rubbish being dished out, unfortunately by Defence Ministry & Law Minister. No such contract or MoU was ever signed between Dassault Aviation & Shri MukeshAmbani's company. They have the records. We challenge the Law Minister & Defence Minister to make any such record public. As there is no record, the lies will be exposed.

(ii) Truth is that, Dassault Aviation had entered into a Work-Share arrangement with PSU, HAL. This is proved by

(a) In Annual Report 2013-14, Mr. Eric Trappier, CEO Dassault states that 'Our main partner is Hindustan Aeronautics Limited (HAL)' **[Please See Page 3 of Annual Report, Annexure A2]**

(b) On **25th March 2015**, (just 17 days before PM Modi announced the purchase of 36 Rafales on 10th April, 2015), Dassault CEO, Mr. Eric Trappier, in the presence of Chief of Indian Air Force & HAL Chairman, stated that negotiations with HAL are at final stage and "contract finalisation and signature would come very soon"

[**Please See Annexure A3**]

(c) On **13th March 2014**, a **'Work share Agreement'** was signed between HAL and Dassault Aviation. [**Please See Annexure A4**]

क्लेम नंबर 2, पूरे मामले को भटकाने के षड़यंत्र के तौर पर रक्षा मंत्रालय ने भी लगभग एक घंटा पहले एक बयान में और उसके बाद गैर-कानूनी कानून मंत्री ने भी ये कह दिया कि फरवरी, 2012 में ही दसॉल्ट एविएशन और मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का ऑफसैट कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझौता हुआ था। और एक अखबार की कतरन को भाजपा के कार्यालय और देश के कानून मंत्री दे रहे हैं।

तीन जवाब दें दें। पहली बात, ये पूर्णतय: असत्य, शरारतपूर्ण और षडंयत्रकारी है। ना ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ऐसा कोई समझौता हुआ, मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और दसॉल्ट एविएशन के बीच में। हम चुनौती देते हैं, सरकार आपकी है, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आपके पास है, कागजात सब आपके पास हैं, हम चुनौती देते हैं, रवि शंकर प्रसाद जी, निर्मला सीतारमन जी, आदरणीय मोदी जी अगर कोई ऐसा समझौता हुआ है तो आप वो कागज सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि वो कागज हैं ही नहीं, इसलिए झूठ, शरारतपूर्ण और षड़यंत्रकारी तरीके से पूरे मामले को भटकाने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सामने लाईए वो कागज।

सच्चाई ये है कि समझौता हुआ था, दसॉल्ट एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी के बीच में। 2013-14 की अगर दसॉल्ट एविएशन की एनुअल रिपोर्ट जो एक statutory फाईलिंग है, फ्रांस में जो दसॉल्ट कंपनी ने की है, अगर वो कानून मंत्री पढ़ लेते तो शायद उनको इस तरह का षड़यंत्रकारी झूठ ना बोलना पड़ता। और उसमें साफ तौर से लिखा है और उसकी एक प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं।

Eric Trappier का इन्ट्रव्यू बाकायदा दसॉल्ट एविएशन की 2013-14 की रिपोर्ट में है और उसमें वो कहते हैं कि हमारे प्रिंसपल पार्टनर HAL हैं।

बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 25 मार्च, 2015 को मोदी जी के 10 अप्रैल, 2015 के समझौते से 17 दिन पहले Eric Trappier, CEO दसॉल्ट एविएशन हिंदुस्तान की इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष, HAL के चेयरमैन के साथ HAL की फैक्ट्री में जाते हैं, बैंगलोर और वहाँ वो क्या कहते हैं, उसकी वीडियो हम आपको जारी कर रहे हैं।

17 दिन पहले, 10 अप्रैल, 2015 से 25 मार्च, 2015 को HAL के चेयरमैन और इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष की मौजूदगी में Eric Trappier ये कहते हैं और उसका वीडियो और बयान, दोनों हम आपको जारी कर रहे हैं।

तीसरा, 13 मार्च, 2014 को, वर्क शेयर एग्रीमेंट साईन हो गया था, HAL और दसॉल्ट एविएशन के बीच में। ये कौन कह रहा है, ये HAL के चेरयमैन कह रहे हैं, जिन्होंने चुनौती दी है देश की रक्षा मंत्री की कि आपमें हिम्मत है कि फाईल झूठ नहीं बोलती, आप उन फाईल को उजागर कर दीजिए।

क्लेम नंबर 3, *Law Minister claims that price of Rafale aircrafts is 'secret' and cannot be disclosed.* और उसी सांस में कहते हैं कि ये प्राईस कम भी है। एक तरफ आप कह रहे हैं सिक्रेट है, बताया नहीं जा सकता और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, कम, कौन सी बात सच है? ये भी बहुत बड़ा झूठ है। कानून मंत्री ने खुद माना कि यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जो दिया था, 126 जहाज का, वो 12 दिसंबर, 2012 को खुला था। कानून मंत्री ने फिर ये भी मान लिया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार कर कि उसमें L-1टेंडर में राफेल आया था, कांग्रेस के समय में। उसकी लागत 526 करोड़ थी और मैं आपको French

Senate के कागज, जो statutory फाईलिंग French Senate के अंदर दी गई है, मैं आपको वो जारी कर रहा हूं।

दूसरी बात, 36 एयरक्राफ्ट जो मोदी जी ने खरीदे उनकी कीमत 1,670 करोड़ प्रति जहाज थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दसॉल्ट एविएशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2016 में कहा और अनिल अंबानी जी की कंपनी ने 16 फरवरी, 2017 के प्रेस रिलीज में कहा। मैं वो दोनों कागज आपकी जारी कर रहा हूं।

तो अगर अनिल अंबानी की कंपनी रेट बता सकती है, अगर दसॉल्ट एविएशन रेट बता सकती है तो मोदी सरकार क्यों छुपा रही है? कारण बड़ा साफ है क्योंकि जहाज की कीमत 300 प्रतिशत बढ़ गई।

क्या बताएंगे कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कि भारत सरकार के खजाने से, जो देश की जनता का खजाना है, 41,205 करोड़ रुपया अतिरिक्त क्यों लूटा गया, कीमत अदा क्यों की गई?

Claim 3: *Law Minister claims that price of Rafale aircrafts is 'secret' and cannot be disclosed. In the same breath, he claims that price of Rafale aircrafts is less .*

Answer 3: (i) As admitted by Law Minister, the international tender for purchase of 126 aircrafts was finalized by Congress-UPA on 12.12.2012. Even Law Minister has said that Rafale was L1. This price was Rs 526 Cr. [**Relevant extract from the '2014 Finance Bill: Defense: Equipment of the Forces and Technological Excellence of the Defense Industries' from the French Senate is attached as Annexure 4A (French) and Annexure 4B (English). Link is** - http://www.senat.fr/rap/a13-158-8/a13-158-814.html]

(ii) Price per aircraft of 36 aircrafts bought by Modi Govt is Rs 1670.70 Cr per aircraft or Euro 7.5 Billion. This price has been disclosed by Dassault Aviation in its Annual Report, 2016 and by Reliance in its Press Release dated 16.2.2017 [**Annexure A5 & Annexure A6**] What is the reason for a 300% increase in the price? If Dassault& Reliance can tell the price, why can't Government of India?

(iii) Why did Modi Govt, thus pay an extra amount Rs 41,2015 Crore out of the public exchequer for 36 Rafale aircrafts?

क्लेम चौथा, कानून मंत्री ने ये कहने का प्रयास किया तोड़-मरोड़ कर कि कांग्रेस के समय में खरीदे गए जहाज में ना गोली थी, ना बौम्ब था, ना पिस्तौल थी, ना मिसाईल थी, Joy ride के लिए खरीदा गया था। इससे बड़ा झूठ और शरारतपूर्ण षड़यंत्र एक गैर-कानूनी कानून मंत्री के द्वारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कानून मंत्री कांग्रेस के नहीं, इंडियन एयरफोर्स की credibility, competence & integrity को चुनौती दे रहे हैं, जो एंटी नेशनल है।

RFP जो 28.8.2007 को जारी हुआ था, जैसा कानून मंत्री ने बताया। अगर वो उसे पढ़ लेते बगैर पढ़े ना आते पत्रकार वार्ता करने, तो वो ये पाते कि उस RFP में ही लिखा है, कि it's a fully loaded Aircraft, that's mean weaponry, avionics and 'Transfer of Technology'. जब RFP बनाया इंडियन एयरफोर्स ने 'Air Staff Qualitative Requirements' ASQR, बनाए, जिसमें उन्होंने क्या Specific